Irregular diversion of Milk by DMS depot Managers

148. SHRI SITARAM KESRI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware about the difficulties being faced by the people in the Capital in getting milk at DMS Depot because of the large supplies of milk being irregularly diverted to certain people in bulk for onward distribution to consumers on hefty commission;

(b) whether it is a fact that there is no effective control by officers on Depot Managers to check such malpractices or there is some collaboration between them and the distributors; and

(c) if so, what concrete steps are proposed to be taken to eliminate such irregular diversion of milk?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) The price of DMS milk being far below that of other suppliers in the market, there is very heavy demand for DMS milk, which brings considerable strain on DMS's milk distribution system. However special care has been taken to distribute DMS milk from its booths on first come first served basis. Residents Welfare Associations and Depot Advisory Committees are being increasingly associated with the distribution process so as to ensure fair distribution of milk.

दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधायें

149. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धन और सीमान्त किसानों को सुविधायें दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) जी, हां।

दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन०पी०डी०पी०) के तहत प्रमुख आदानों पर गरीब तथा सीमान्त किसानों सहित सभी प्रकार के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, छोटे/सीमान्त किसानों को वरीयता दी जाती है। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	केन्द्रीय आवंटन संशोधित/ सं०आ०	(रुपये लाख में) निर्मुक्तियां
1996-97	3543.00	3542.00
1997-98	3431.00	3431.00

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

अण्डों का उत्पादन

150. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मुर्गी के अंडों के उत्पादन का क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था और यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया;

(ख) क्या मुर्गी-दाना एवं अन्य औषधियों की कीमत अधिक होने के कारण मुर्गी के अंडों का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है; और

(ग) क्या भारत सरकार मुर्गी पालन व अंडा उत्पादन को उत्पादकों के लिए लाभ दायक व्यवसाय बनाने के लिए कोई योजना बना रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अण्डा उत्पादन का लक्ष्य 30 बिलियन था जिसकी तुलना में लगभग 28 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

(ख) कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है तथा आहार और दवाईयों की लागत उनमें से एक कारक है। आहार तथा दवाइयों के उच्च मूल्यों के